से बैठ जाइए। मिस्टर कल्पनाथ राय, इस हाउस में प्रधान मंत्री आते हैं, बड़े-बड़े सीनियर मिनिस्टर्स आते है जो आप से भी सीनियर है। जूनियर मिनिस्टर आते है। इस हाउस की एक गरिमा है। आप सवाल का जवाब दे रहे थे और आपने चेयर की परमिशन से जवाब दिया है इसलिए आपको चेयर से परमिशन लेकर ही जाना चाहिए था। हम लोग सारे दिन तो आप को बैठाने वाले नहीं थे। आपने जवाब दिया, आपने शेर पढ़ा and you walked out. This is not the way. It has never happened in this House. As I ask the Members to keep the dignity of this House, I request you also to keep the dignity of this House. I have presided when Mrs. Gandhi and Shri Rajiv Gandhi and two other Prime Ministers and the present Prime Minister have been here. It never happened during the time when I was presiding that a Minister would just walk out. It is part of a parliamentary democracy: the opposition is going to oppose you and it is your responsibility as a Minister to reply to the best of your ability. By running away you are not going to shed your responsibility as a Minister. You just say that on the basis of whatever information you had, you replied. I think it is proper that you should apologise to the House.

SHRI KALPNATH RAI: I apologise. Madam, I am sorry.

THE DEPUTY CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Now the House is adjourned for lunch till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at ten minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-one minutes past two of the clock,

THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

उपसभापति: आज बैसे तो हम लोगों का प्राइवेट मैंबर्स का लैजिस्लेटिव बिज़िनेस है, मगर विद्याचरण शुल्क जी, पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर हाऊस में आए हुए है। आपने जो शंका उठायी थी कि एक करोड़ रुपये का क्या होगा, हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में ये सब मैंबर्स को चिन्ता थी और उसके बारे में हमने पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर से कहा। हम लोगों को इस बात की खुशी है कि विद्याचरण शुक्ल जी आज हाऊस में आए हैं। आप आऊस खत्म होने से पहले बताइए कि क्या होगा?

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): संशोधन, हमने यह नहीं कहा कि हमको मिलेगा, हमारे द्वारा पब्लिक को मिलेगा। हम क्यों लेंगे?

उपसभापति: अब आप इतनी बारीकियों में जाएंगे। एक बात में बताऊं संघ प्रिय गौतम जी कि जितनी आप बारीक छानेंगे, उतनी ही उसके अंदर मिट्टी मिलती है। देखिए चुप-चाप रहिए।.....(**व्यवधान**).....पैसा जो मिल रहा है, वह आपके लिए नहीं मिल रहा है, हमारे लिए नहीं मिल रहा है, इस देश की जनता के लिए सरकार दे रही है, जिस काम के लिए यह जरूरी है। तो मंत्री जी इस पर बोलने के लिए आए हैं।

श्री सुरेश पचौरी (मध्य प्रदेश): महोदया, प्राइवेट मैंवर्स बिल का जो इंट्राडक्शन है, उसमें पांच मिनट लगेंगे।

उपसभापति: यह हो जाए, एक मिनट में। कोई क्लैरीफिकेशंस नहीं होंगे, मंत्री जी बोलकर चले जाएंगे, चार लाइन का है, फिर सारा इंट्राडक्शन करा देंगे।

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा): महोदय, मंत्री जी यहां बयान देने के लिए आए हैं, इसके लिए हमें आपका आभार प्रकट करना चाहिए, जिन्होंने यह इश्यू क्लिंच कर दिया और मंत्री जी को यहां आने पर मजबूर कर दिया, वरना यह मुद्दा तो निकल गया था, हम लोग तो चीख-चाखकर, बोल-बालकर रह गये थे। यह तो आपने सरकार को निर्देश दिया और कहा कि सदन का सत्र समाप्त होने से पहले मंत्री जी आएं और बोले हम, बल्कि सभी संसद सदस्य आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं कि आपने मंत्री जी को बुला दिया।

उसभापति: हम तो आभार प्रकट करते हैं कि मंत्री जी लेकर आए हैं। अच्छी चीज़ किसी की भी वजह से हुई, दिया तो प्रधान मंत्री जी ने।.....(**व्यवधान**)

STATEMENT BY MINISTER

M.Ps. Local Area Development Programme

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI VIDYACHARAN SHUKLA): Madam Deputy Chairman, I would like to clarify that it has been decided that a separate Fund would be constituted for M.Ps. Local Area Development Scheme in order to streamline its im- plementation and to remove the difficulties experienced by the hon. Members of Parliament. Suitable amendments would also be made in the Guidelines in this regard.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): जिलों में पैसा कब तक पहुंच जाएगा?....(**व्यवधान**)

उप सभापति: अभी कोई क्लैरीफिकेशन नहीं। आप बैठिए।

SYED SIBTEY RAZI (Uttar Pradesh): Madam Deputy Chairman, on behalf of my Party, I thank the hon. Minister....

SHRI SATYA PRAKASH MALVIYA (Uttar Pradesh): On behalf of the whole House....*(Interruptions)*

SYED SIBTEY RAZI: Madam, we are grateful to Shri Rameshwar Takur and Shri Shukla. *(Interruptions)* We are grateful to them for clarifying the position. This would enable the implementation of the essential projects as early as possible, in the different areas. We are

grateful to the hon. Prime Minister. He has tried to clarify the misunderstanding which was created in certain quarters. We are very happy and we thank the Prime Minister. He had not only thought about the development of the different areas, but he had also acted upon it. Now, the misgivings which had been created during the past one month on this score would be removed:

श्री संघ प्रिय गौतम: मैं अपनी पार्टी की ओर से दरख्वास्त करूंगा कि वह तारीख निश्चित कर दें जब तक यह धन जिलों में पहुंच जाएगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: गाइड लाइन कब तक जारी होगी?.... (व्यवधान) क्योंकि फ्रानेंशियल इयर पहली अप्रैल को शुरू हुआ था। चार महीने ऐसे ही बीत चुके हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, इसलिए गाइड लाइन कब तक होगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा): कम से कम मंत्री जी यह कह दें कि एक करोड़ रुपया प्रति एम०पी० की दर से होगा, यह सेपरेट फंड है, जरा इतना बता दें। मंत्री महोदय ने हमारे साथ एक डिसक्शन में दूरदर्शन पर इंटरव्यू में यह कहा था लेकिन उसके बाद न जाने कहां से यह सारा विवाद खड़ा हो गया। यह जो आपने कहा है कि सेपरेट फंड वुड बी कंस्टिट्यूटेड, इसमें कोई एंबीगुएटी है। आप यह बता दें सपरेट फंड एक करोड़ रुपया प्रति एम.पी. की दर से होगा।...(व्यवधान) ऐसा न हो कि फिर कल कह दें कि कम है। तो आप बता दें कि एक करोड़ रुपया प्रति एम०पी० के दर से होगा।

DR. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh): Madam, it should be timebound. What is the time limit? *(Interruptions)* It is a promise without time. Again, it is a promise without any time limit. *(Interruptions)*

श्री ओ०पी० कोहली (दिल्ली): उपसभापति महोदया, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

उपसभापति: सुनिये जरा।

श्री ओ.पी. कोहली : यह इसी से संबंधित है।

उपसभापति: आप बैठिये। वे दुबारा फिर खड़े हों यह कोई तरीका नहीं है। उनको बोल लेने दीजिये। जब कोई तोहफा लेकर आते हैं तो उनको सुनते हैं।

SHRI VIDYACHARAN SHUKLA: Madam, if hon. Members have certain queries, it would be better if they are allowed to raise their queries. Then, I can reply to all the queries at the end.

श्री ओ०पी० कोहली: हमें दिल्ली की सरकार की ओर से एक पत्र आया है। इस पत्र के दूसरे पैराग्राफ में लिखा गया है कि:

This is in regard to the M.Ps. Local Area Development Scheme.

इसके सैकंड लिखा गया है कि:

'The Government of India has given the Government of Delhi a provision of Rs. 5 lakhs per M.P. for the financial 5 year 1993-94. It was given to us only on the 31st March, 1994, and the scheme would be implemented during this year only'.

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह पांच लाख रुपये ...(व्यवधान)... फिर अभी तीन-चार दिन पहले दिल्ली सरकार के यहां एक बैठक हुई तो उसमें हमको कहा गया कि आपको केवल पांच लाख रुपया....

उपसभापति: कोहली जी, आप जरा लेट आए। एक मिनट मैं आपको स्पष्ट करती हूं, मिनिस्टर साहब को बोलने की जरूरत नहीं है। इस हाउस में तीन दिन पहले मैम्बरों ने शंका उठायी कि अभी तक एक करोड़ रुपया मिल नहीं रहा है, जैसे आपके दिल्ली में हुआ। इस पर सब मैंबरों ने अपनी परेशानी का इजहार किया। इसीलिये पार्लियामेंटरी एफियर्स मिनिस्टर शुक्ला जी कहने के लिये आये हैं। जो स्टेटमेंट पढ़ा गया है उसे पढ़ लीजिये। यह उसमें भी कवर होता है।

श्री ओ०पी० कोहली: मेरा केवल प्रश्न यह है इस वर्ष एक करोड़ रुपया मिलेगा या पांच लाख रुपया मिलेगा।

उपसभापति: मैं आपसे यही अर्ज कर रही हूं कि कृपया हाउस में जो स्टेटमेंट रखा गया है उसको पढ़ लीजिये, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जायेंगी।

SHRI GOVINDRAO ADIK (Maharashtra): Madam Deputy Chairman, I associate myself with the sentiments expressed by the Deputy Leader of the Party, Syed Sibtey Razi. We congratulate and thank the hon. Prime Minister for having cleared the confusion which was created by the earlier orders of the Government.

श्री सुरेश पाचौरी (मध्य प्रदेश): महोदया, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा जो उन्होंने स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अन्तर्गत जो हमारे संसद सदस्यों को राशि उपलब्ध करायी जानी थी, उसके संबंध में उसके जो दिशा-निर्देश और सिद्धांत हैं, उसमें उन्होंने आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया। लंबे समय से हमारे संसद सदस्यों को जो परेशानियां हो रही थीं उसका इससे निदान निकलेगा, ऐसा मेरा विचार है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जैसे लोक सभा के सदस्यों को यह सुविधा उपलब्ध है कि वह जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और उस क्षेत्र में दो या तीन जिले भी आते हैं तो उन जिलों में चलायी जाने वाली योजनाओं के लिये वह इस योजना के अंतर्गत राशि आवंटित कर सकते हैं या वैसी ही सुविधा राज्य सभा के सदस्यों को भी उपलब्ध करायी जायेगी? यदि वे दो-तीन जिलों का चयन करना चाहें तो क्या वे कर सकते हैं?

दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि पहले यह राशि राज्य सरकारों को भेज दी जाती थी। अब क्या सरकार यह निर्णय लेगी कि यह राशि सीधे जिलाधीशों यानी कलेक्टरों को भेजी जाये ताकि जो अनावश्यक विलम्ब होता है वह विलम्ब न हो सके।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Madam Deputy Chairman, the matter was agitating the minds of hon. MPs. The hon. Prime Minister, the hon. Minister for Parliamentary Affairs, the Minister of State for Rural Development and also the Finance Minister have taken steps to see that the problem of allocating funds under a separate head under the Local Area Development Scheme is resolved as suggested by the hon. Member. Now there is no difficulty so far as funds are concerned. On my own behalf and on behalf of my colleagues, I thank them for this. I have two clarifications to seek.

One is, there is a practical problem. It you go through the scheme, you will find that it is said that if the schemes are presented by the Members of Parliament, the district authorities have to accommodate those schemes as far as possible. The wording is "as far as possible". Therefore, what will happen is, the district authorities may completely refuse them, saying that is not possible for them accommodate them. Therefore, this wording should not be there. You may give a proper guideline that only under this category they will be accepted. But if these words are there, they will give a discretion to the district authorities not to accept the proposals given by the Members of Parliament even if there is a burning problem in the constituency. I also wrote a letter to the hon. Rural Development Minister about this, but I have not so far received any reply to it. Secondly, there are some primary schools in the MPs' areas, which are aided by the State Governments. The State Governments are giving grants for these schools and these schools are functioning well. Further funds are required for strengthening these institutions. But these schools are not given under this category. That has been the worry of the Members for a long time. Therefore, these schools also may be included in this category because the Members of Parliament have got a compulsion to help these institutions in their constituencies also.

There are the two clarifications that I seek. I would request the hon. Minister to consider these and announce about them now.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Madam Deputy Chairperson, I am happy and I compliment the Government that now they are having a separate fund for the MPs under a separate head. My only worry is, this is the month of August and the guidelines will take one more month. Thus six months will pass. So I want to know from the hon. Minister whether, if we are not able to spend the funds this year, they will be allowed to be carried forward to the next year or not. Now, you have allowed Rs. 5 lakhs to be carried forward to the next year. Similarly, if the funds are not spent in the current year, I would like to know whether they would lapse or would be allowed to be carried forward to the next year. If they are not allowed to be carried forward, it will not be possible to spend the funds within these six months. Secondly, my good friend, Mr. Pachouri, talked about the districts and said that they should be given for three districts. Madam, I am so fortunate that I have a sub-urban district and there are three Parliamentary constituencies in my one district. Therefore, I will be able to cater to three Parliamentary constituencies. But, as far as Members of Rajya Sabha are concerned, let it be only one district so that it would be beneficial for us.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Desai, in that district there are at least two Members of Parliament—you and I...*(Interruptions)*.....

SHRI JAGESH DESAI: Therefore, I request them to allow the funds to be carried forward to next year, and let that be announced today.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Madam, the hon. Minister has announced that it is a separate fund. I do not know whether it is under a separate head. Anyway, it is linked to the State funds because they were requested and pressurized by the State Governments to allot the funds to the State Governments. And they say, we will refund the amount next year.

The second point is, my hon. colleague has requested that these funds be allowed to be carried forward to the next year. I would request the hon. Minister to see that we are allowed to accumulate this fund for the full term and utilize it next year. I make this request because the elections are almost declared now in my State and we will not be able to utilize the funds now. So, what do we do with those funds now? And I think the Election Commission will also issue some strict directives about it.

Thirdly, it is mentioned that these projects have to pass through the Public Works Department.

Just to give an example, I got estimates for a culvert from a private party as well as the PWD. The project was cleared by the PWD for Rs. 4.65 lakhs, whereas the private party gave the estimate for Rs. 85,000. Why should we allow this Government Department to fleece the public exchequer? Why should we pay so much amount to it when the same work can be done by a private party for Rs. 85,000. They

form a cartel and corner this amount. Will this schemes be amended to see that private parties who can do the same quality of work are given these works. ...*(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am coming to you one by one. It is not a party matter: it is a matter of MPs.

SHRI HIPHEI (Mizoram): Madam, I have a problem of my own. As soon as a decision was taken on this, I invited opinions from local leaders. I told them, "This is your money. It has to be spent properly. You have to tell me what schemes are required." I got them and I submitted them long back. All the schemes are pending with the District Collector. I request that this should be hastened. This is one point.

Another point is that the schemes should be in conformity with the local schemes of the State Government. For example, for construction of a water tank, according to the norms of the Govt. of Mizoram, Rs. 5,000 are general spent for a water tank. We have to create durable assets. How can we create durable assets worth Rs. 5000. This may kindly be amended.

Mr. Narayanasami has mentioned another point. There are aided schools. There are two types of aided schools one, deficit, and the other, non-deficit. The State Government cannot help them. We want to help aided schools. When the scheme is amended, this may kindly be included....

Another thing is that one scheme should not exceed Rs. 10 lakhs. We want to create durable assets. We would like to have a sports.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Complex.

SHRI HIPHEI:.... complex. That involves Rs. 20 lakhs or Rs. 30 lakhs. So, this ceiling should be relaxed so that more than Rs. 10 lakhs can be spent on one scheme.

Thank you.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, मैं पूरी सरकार का और विशेषकर ग्रामीण राज्य मंत्री श्री रामेश्वर ठाकुर जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं क्योंकि इस विषय पर जब जब मैं उनसे बात किया करता था पिछले दो महीने में कम से कम 10 बार मैंने उनसे बात की होगी—बराबर उन्होंने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान न होइये। मैं बहुत जल्दी सारा मामला तय करके सदन को बता दूंगा। इसलिए मैं विशेष रूप से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

दूसरा, दिशा निर्देश की जो आज बात की गयी, इसके संबंध में निश्चित रूप से जल्दी करनी चाहिए सरकार को क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया कि यह वित्तीय वर्ष पहली अप्रैल से शुरू हो गया है। चार महीने बीत गए हैं। इन चार महीनों के बीच में कम से कम उत्तर प्रदेश में किसी स्कीम के अंदर कोई काम नहीं हुआ है क्योंकि जिलाधिकारी सबसे यही कहते थे कि हमारे पास रुपये का एलोकेशन सरकार की तरफ से नहीं हुआ है इसलिए हम कर नहीं सकते हैं। वित्तीय वर्ष जल्दी खत्म हो जाएगा—अगले 7-8 महीने के अंदर तो दिशा निर्देश जल्दी सरकार बना करके प्रत्येक प्रदेश सरकार के पास भेज दे और उसकी प्रतिलिपि सारे सांसदों के पास भेज दें जिसे कि हम लोगों को काम कराने में सुविधा हो और उसको जल्दी करा सकें।

SHRI G.G. SWELL (Meghalaya): Madam, in my area, one parliamentary constituency consists of four districts because it is a hilly place. I have written to the Prime Minister. I have talked to the Minister of Rural Development also suggesting that exception should be made in the case of hilly parliamentary constituencies. As it is, now I have confined myself to only one district. The people of the other three districts also want something to be done in those districts, but I cannot do anything for them. You make an exception for constituencies in hill areas which are farflung. Each constituency covers many districts. Allow us to use this moeny for all those districts in one constituency. Or, as you were mentioning that you were considering it, allow the MPs to adopt the district by rotation, that is, to adopt one district this year and to adopt another district the next year.

SHRI JAGESH DESAI: It is there.

SHRI G.G. SWELL: It is not there. They have not clarified it. Let the Minister clarify this point also.

श्री जलालुदीन अंसारी (बिहार): उपसभापति महोदया, यह जो एम-पीज़ लोक एरिया डिवैलपमेंट स्कीम के संबंध में भ्रम था उसको दूर करने के लिए यह जो बयान आया है और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यह एक अलग स्कीम होगी और इसको लागू करने के लिए वह सूटेबल अमेंडमेंट लाने जा रहे हैं तो इसका हम स्वागत करते हैं।

मुझे यह कहना है कि एक करोड़ रुपये की बात जो कही गई है तो उसको सीधे कलैक्टर के यहां जाना चाहिए । आप स्टेट गवर्नमेंट को बहुत जगह दे देते हैं। तो वह फाइनांशेली इतना गड़बड़ है कि उनके पास पैसा ही नहीं है, इस पैसे को दूसरे मद में खर्च कर देते हैं, तब यह एम-पीज़ लोकल एरिया डिवैलपमेंट स्कीम का क्या होगा? इसलिए डाइरेक्ट आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दें और यह

गाइडलाइन के मुताबिक है कि जिला योजना के अंदर यह एक अलग़ यदि स्कीम है तो उसको जिला योजना के मातहत नहीं रखा जाना चाहिए। गाइडलाइन में इस बात को क्लीयरकट जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि एक समय बीत गया इस साल का तो लैप्स नहीं होना चाहिए और दूसरे सदस्यों ने भी कहा है कि उसको आप अगले फाइनांशेल ईयर, अगले वित्तीय वर्ष में उसकी पूर्ति आप कीजिए और गाइडलाइन को बहुत ही शीघ्र सैन्ट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी दे दीजिए और गाइडलाइन में सुधार करके एम-पीज़ के लिए भी हो तो हम समझते हैं कि इस रूप में यह काम होना चाहिए।

दूसरा आप राज्य सभा के सदस्यों को सिर्फ एक जिला में बांध देते हैं, यह अवसर होना चाहिए कि राज्य सभा के सदस्य एक वित्तीय वर्ष में एक जिला को चुन सकते हैं, दूसरे वित्तीय वर्ष में दूसरे जिला को भी चुन सकते हैं, यह प्रोविज़न, यह व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री जलाल उद्दीन अंसारी "बहार": आप सभापति महोदय, यह जो एम-पीज़ लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के सम्बन्ध में भरम था उस को दूर करने के लिये यह जो यहां किया है और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि यह अलग स्कीम होगी और उस को लागू करने के लिये वह सप्लीमेंटल इस्टीमेंट लाने जा रहे हैं तो इस का हम स्वागत करते हैं। मुझे यह कहना है कि एक करोड़ रुपया की बात जो कही गई है तो उस को सीधे कलैक्टर के यहां जाना चाहिये। आप स्टेट गवर्नमेंट को बहुत जगह दे देते हैं तो वह फाइनांशली इतना गड़बड़ है कि उन के पास पैसा ही नहीं है। इस पैसा को दूसरे मद में खर्च कर देते हैं। तब यह "एम-पीज़ लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम" का क्या होगा। इस लिये डाइरैक्ट आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दें और यह गाइडलाइन के मुताबिक है कि यह जिला योजना के अंदर यह एक अलग

THE DEPUTY CHAIRMAN: Because we do not want to waste the time of the House.

SHRI MD. SALIM: As far as my CPI(M) party is concerned, we think the money earmarked for this scheme should be routed through the State Governments. We have a very well defined block level, district level planning arrangement in West Bengal. That is why we feel that there should not be a dual system. We also demanded that money for this scheme should be earmarked separately. There should be a separate fund. We welcome this decision. This should be routed through the State Government; otherwise, it would create a lot of problems.

My second point and the last point is that Members have faced some trouble and problem with regard to this scheme. So, we have voiced it here. Only then the Government came out with this sugestion. We have accepted this. I would like to say that whenever the Government annouces a populist scheme, they should do a lot of home work. A lot of people face problems in the rural areas, in the urban areas and at the district level with regard to several *Mahila Yojana, Navjawan Yojanand Children's Yojana.* Since Members of Parliament were involved in this MPs LAD scheme, we could voice our anger, or anxiety and our problems here. You also took it up. In future when the Govt. announce any populist schemes, I hope that they will take all these factors into account. They should announce a scheme only after doing a lot of home work. (Ends)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Mr. Salim. I want Members to make some new points. If it is the same point, then, there is not point.

SHRI G. SWAMINATHAN (Tamil Nadu): Madam, it is an old point. Any how, I want to thank the Government for introducing this scheme. Madam, you have rightly said that it is not a party matter but it is a matter of Members of Parliament Members of Parliament belonging to various parties are there in the State. There is already a complaint, "I belong to this party, when I tell about some scheme to the District Magistrate, he is not helping me." This kind of problem is there. The hon. Member belonging to the CPM said that this scheme should be routed through the State Government. Fortunately, for them the CPM Government is there. When the Congress Government comes into power there, I do not know whether he will say: "Route the money through the Congress Government." Perhaps, he may change his opinion. So, what I feel is that whichever party's Government may be there, it is the MPs' scheme and all the parties are concerned with this scheme. The matter regarding the embargo imposed by the Chief Election Commissioner was raised. This is a very important matter. Otherwise, the Chief Election Commissioner can say that any amount spent by the Member will come within the purview of the Election Commission. My feeling is that it should remain with the Government and it can come within the purview of the Election Commission only when the Government announces a scheme before the elections. The MPs Area Development Fund, according to me, should not come within the embargo of the Election Commission. So, I would request the Government to clarify this point. Then they say that according to the policy laid down, we should come under the district plan and the State Plan. When we start inquiring from them as to what the district plan is, they are not able to satisfy us. In fact, many districts do not have any plan. So, the problem as to how to conform within a particular plan becomes a bit difficult for us. Another point is, now you have given it to the discretion of the District Collectors and the District Collectors create problems for us. Suppose, they refuse to entertain our request, then who is the other authority to whom we can appeal? There is no provision for an appeal. If the District Collector says: "No, it is not approved," then there should be some person to whom we can appeal that the District Collector is not right in refusing a particular scheme.

Lastly, I come to the aided institutions. In Tamil Nadu, as it has been rightly said by Narayanasamy, many institutions are aided by the Government. The Government give aid to them. In our place, we have got only one government school. Nowadays, not many people go to government schools. Now, the Government aided institutions are coming up nicely and the Government is not only giving money, but also giving more and more money to these institutions. When the Government

itself gives money to those institutions, what is wrong if the MPs also give? I would request the hon. Minister to clarify all these points in the interest of the MPs Area Development Fund.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we have to take up Private Members' business Mr. Muthu Mani, if there is something new to speak, you can speal. Otherwise, simply say, "Thank you." ...*(Interruptions)*... This is very funny. If somebody was not bringing the money, I understood that point. Everbody was raising his objection, concern and worry and I joined you. But, now, when someone has come with the money and with the best proposal that they are willing to change their scheme, even then, everybody wants to speak!

SHRI G. SWAMINATHAN: Madam, our problem starts when the money comes. When there is no money, there is no problem.

SHRI S. MUTHU MANI (Tamil Nadu): Madam, I want to make one submission. I welcome the statement made by the Minister. I suggest one amendment in the scheme. Madam, we, the Members of Rajya Sabha, belong to the State and we represent the whole State. I would like to make one submission for the kind consideration of the hon. Minsiter. In the guidelines, it has been stated that a Member of Rajya Sabha can select a particular district from which he is originally said to have been elected for implementing the scheme. My point is that he is representing the whole State. So, a Member of Rajya Sabha should be allowed to select a scheme which can be implemented not in a particular district but throughout the State.

SHRI SANATAN BISI (Orissa): Madam, as per the last sentence of the statement, it has been stated: "Suitable amendments will also be made in the guidelnes in this respect." Madam, we have taken oath recently. When we went to our constituency areas, the Collector gave us a copy of the guidelines. As per the guidelines, we have already, submitted out plan and that plan has also been approved and wide publicity has been given to that effect. So, what I submit is that the guidelines which were prevalent there and no the basis of which we have given our proposals, those proposals should not be affected. That is what I wanted to say. *(Interruptions)*

SHRI S.K.T. RAMACHANDRAN (Tamil Nadu): Madam, already four-five months have elapsed since the financial year started. But, no funds so far, have been released. If they are not quick in releasing the funds, it may have a chance to lapse.

SHRIMATI MIRA DAS (Orissa): Madam, earlier Rs. 5 lakhs were sanctioned. The work has already been started. पर बात यह है कि वह एक करोड़ कि स्कीम देने का तो आ गया है हमारी स्टेट गवर्नमेंट से, कि आप एक करोड़ की स्कीम का ले लीजिए। ऐसा करके प्लानिंग कोर्डिनेशन डिपार्टमेंट से स्कीम के लिए लेटर आ गया है। अब जैसे हम लोग स्कीम भी बना ली है, अगर रुपया टाइम पर नहीं पहुंचता, मैडम, तो स्थिति क्या होगी? मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, JAGAT SINGH PUR, that is the flood affected district. Unless the money reaches there in time, the purpose will is not served. Madam, I cannot help if the Government really wants to help the people, the money should reach in time. I also request the Minister to make it time-bound programme. Thank you.

उपसभापति: राघवजी, आप कोई नई बात कहने वाले है तो ठीक है मैं मंत्री जी को बोलने को कहूं।

श्री राघवजी (मध्य प्रदेश): मैडम, 17 तारीख को विपक्ष का बहिष्कार समाप्त हुआ और उसी रोज विनियोग विधेयक पर बोलते हुए सबसे पहले मैंने यह मुद्दा उठाया था, जिसका सारे हाऊस ने समर्थन किया था और लोकसभा ने भी इस बात पर चर्चा होकर समर्थन हुआ था। मैं माननीय मंत्री जी को पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज यह घोषणा की, लेकिन इसमें एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि राज्य सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसमें कलेक्टरो के पास यह फंड पहुंचना चाहिए। इस वर्ष 1994-95 के लिए पूरा एक करोड़ रुपया पहुंचना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए कि चार महीना खत्म हो गया और बाकी जो बचे हैं उसके हिसाब से पैसा भेजे। पूरा एक करोड़ एक साल का जिलाधीश के पास पहुंचना चाहिए। वहां पर एक सैल बनना चाहिए, जिसमें इंजीनियर एक असिस्टैंट, एक ओवरसीयर, एक क्लर्क वगैरह सब होने चाहिए।

उपसभापति: लंबे सजेशन आप लिखकर भेज दीजिएगा। मलकानी जी बोलिए।

श्री राघवजी: मेरा निवेदन यही है कि यह सेल वहां जल्दी बन जाए ताकि काम जल्दी शुरू हो सके। धन्यवाद।

SHRI K.R. MALKANI (Delhi): Madam, the last sentence of the statement is "Suitable amendments would also be made in the

guidelines in this regard." I would like to request the Minister to make it clear as to when we should expect these suitably amended guideliens. We would like to know whether it will take one week, one month or one year. I say this because of my experience. The Prasar Bharati Bill was passed four years back and the President also gave his assent four year ago. But it has not been implemented on the ground that rules are being made. So, the Minister must be very precise. Thank you. (Ends)

श्री गोविन्दराम मिरी (मध्य प्रदेश): मैडम, धन्यवाद देने के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि स्कीम तो अच्छी अच्छी बनाई गई है, पहले भी कहा गया था, गाइडलाइन भेजे गए, मगर इंपलीमेंट नहीं हुआ। आज सत्र का अंतिम दिन है, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि यह दिशा निर्देश सिद्धांतों में संशोधन कब लाएंगे? इसका कोई समय निश्चित नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आश्वासन का लॉलीपॉप ही आप हमेशा की तरह यह दे रहे हैं। अच्छा होता कि आप कहते कि स्कीम के साथ दस लाख की पहली किस्त आपके पास भेज दी गई है। ऐसा अगर आप कर सके, तो अच्छा होगा, नहीं तो वहीं होगा कि नई बोतल में पुरानी शराब है।

उपसभापति: ठीक है। डा. नोनिहाल सिंह जी। ...**(व्यवधान)**... माथुर साहब, अभी आप तो कुछ न बोलिए, जब इतने बोल दिए है। ...**(व्यवधान)**...

DR. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh): Madam, my submission is that there should be a time-bound transfer of funds to the District Magistrate. Secondly, the contract should be given on the basis of bidding, not to the favourite registered Government contractor. Thirdly, a high level committee comprising MPs and MLAs should be constituted at the district level for this purpose which would advise the District Magistrate and serve as a watch-dog body. That is my submission. Thank you.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): मैडम, हमारा सीधा सा यह कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष इसकी घोषणा की और इस वर्ष केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, माननीय सदस्यगण और देश की जनता सब कन्फ्यूजन में रहे योजना के बारे में। मैं समझता हूं कि आज मंत्री जी ने जो बयान दिया है, यह भी अभी कन्फ्यूजन वाला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक ही प्रश्न स्पष्ट जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, कि कब तक आपके दिशा निर्देश वाले सिद्धांत तैयार हो जाएंगे और कब तक यह रूपया जिलों में पहुंच जाएगा जिला अधिकारियों के पास? मैं स्पष्ट रूप से यही जानना चाहता हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Mr. Naresh Yadav.

SHRI SOM PAL (Uttar Pradesh): Madam, I will ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Som Pal, you are not Mr. Naresh yadav. I called Mr. Naresh Yadav.

SHRI SOM PAL: I will say only one sentence.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let him first speak. I will call you after he finishes his point ...*(Interruptions)*... I said "no'. I have permitted him because he has been asking for a long time.

श्री नरेश यादव (बिहार): बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्षेत्रीय असंतुलन होने की संभावना है। अगर राज्य सभा के सदस्य को एक जिला दे दिया जाता है, प्राब्लम यह है:

उपसभापति: यह भी रिपीट हो गया है।

श्री नरेश यादव: नहीं इस रूप में बात नहीं आई प्राब्लम यह है कि एक जिले से हमारे माननीय सदस्य दो-दो, तीन-तीन एम.पी. हमारे हो गए है। अब वहां तो स्वाभाविक है, कमजोरी है कि लोग चाहेंगे अपने-अपने उसी जिले के लिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि उस जिले को, जहां से हमारे तीन-तीन माननीय सदस्य है, वहां तो तीन-तीन करोड़ से विकास का काम हो जाएगा लेकिन उस जिले में जहां कि पिछले तीन वर्ष से कोई एम.पी. है ही नहीं, एक लोक सभा क्षेत्र मैं जानता हूं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति: ऐसा कैसे हो सकता है?...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश यादव: पार्टी का सवाल इसमें आता ही नहीं है ...**(व्यवधान)**... इसमें पार्टी का सवाल कहां से आता है?

श्रीमती सुषमा स्वराज: कोई न कोई एम.पी. तो होगा?

श्री नरेश यादव: माननीय सुषमा जी, बता रहा हूं कि बिहार के पूर्णिया जिले में पिछले तीन साल से एम.पी. है ही नहीं। ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य: इलेक्शन कमीशन में केस है।

श्री नरेश यादव: इसलिए हमारा यह कहना है कि निश्चित तौर से हम पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारा पैसा पूरे राज्य में खर्च होना चाहिए जिससे संतुलन कायम रह सके। धन्यवाद

(समाप्त)

श्री सोमपाल: उपसभापति महोदया, मेरा यह कहना है कि जो मार्गदर्शक सिद्धान्त निश्चित किए थे सरकार ने,

उनकी पुस्तिका छपी थी, वे बहुत स्पष्ट है और उत्तर प्रदेश का मेरा यह अनुभव है कि वहीं के अधिकारी हम सदस्यों से दिल्ली आकर स्कीमें दस्तखत कराकर ले गए। इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में परिवर्तन करने के बहाने से सरकार विलंब नहीं करे, उन्हीं को रखे, पैसा सिर्फ भेज दे।

उपसभापति: दर्द साहब, आप बोलिए। आप बहुत दिनों के बाद बोल रहे हैं इसलिए बोल दीजिए।

श्री जागीर सिंह "दर्द" (पंजाब): उपसभापति महोदया, हमारे पंजाब में हर गांव में धर्मशाला है और सरकार की गाइडलाइन्स मैंने पढ़ी है, सरकार ने इसमें धर्मशाला की रिपेयर के लिए कोई एमाउंट नहीं रखा। इसलिए मेहरबानी करके रिपेअर के लिए भी पैसा मुकर्रर कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया।

(समाप्त)

THE DEPUTY CHAIRMAN: On behalf of the entire House, I take this opportunity to thank the Minister of Parliamentary Affairs, who has come before us, and the Prime Minister, who took an immediate decision about the issue and also Mr. Rameshwar Thakur, who took up the issue very seriously. I hope in every other issue also, the Governemnt will....*((Interruption)*....

SHRI G. SWAMINATHAN: Madam we thank you very much. But for you, they would not have come before the House so fast. The entire House thanks the Deputy Chairman.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am thanking the Goverment for responding to the issue so fast. Therefore, we must thank the Government...*(interruptions)*...

श्री शारदा महन्ती (उड़ीसा): मैडम, मैं एक सेटेंस बोलूंगा।

उपसभापति: अभी यह हो गया है, बैठ जाइए। अभी मंत्री जी को बोलना है। Now, Mr. Minister.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Madam, we are very thankful to you for conducting this matter in a very fine manner and for allowing an opportunity to the hon. Members to raise various queries. When they go back to their States, they will have no problem in utilising the facility which is extended by the Prime Minister.

First of all, the money will go directly to the District Collectors. it will be use by them under the advice of the concerned Member of Parliament.

Sushmaji wanted to know whether the money was going to very. The money is not going to vary. I hope the hon. Members will be able to use the money for the purposes for which it is designated. We are pursuing the matter. Particularly, Mr. Rameshwar Thakur has been put on the job. He will pursue the matter on a day-to-day basis and see that in a few days-not in a few weeks-the money reaches the District Collectors. I would request the hon. Members to select the schemes and suggest the schemes to the District Collectors. These are the two or three extra advantages which the Rajya Sabha Members have got and which the Lok Sabha Members are grudging. First of all, the Lok Sabha members can spend the money only within their constituencies. The Rajya Sabha Members have been allowed the facility of spending it in their own districts, the entire districts, and a suggestion to rotate the districts is also under our consideration, and after consultations if it is found that rotation of districts is really useful, that may be done. For the time being, all the Members of this House would be required to name a district where they will be indicating the schemes where this money will be utilised.

Another serious problem that the Lok Sabha Members have raised is that whereas the Lok Sabha Members will get only Rs. 5 crores during thier tenure, the Rajya Sabha Members will get Rs. 6 crores during their tenure. It is not really fair. So, we will have to consider how to balance this matter so that the Rajya Sabha Members do not get extra advantage over the Lok Sabha Members....*(Interruptions)*....

श्रीमती सुषमा स्वराज: वित्त मंत्री राज्य सभा के मेंबर है। इसलिए काट नहीं पाएंगे।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: It is my duty to inform the hon. Members of the feelings of the various people who are connected with this matter. I am suggesting nothing from my side. I am not saying that action will be taken in this matter. But this is the feeling that some undue advantage is coming the Rajya Sabha Members...*(Interruptions)*.....

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: This is not undue....*(Interruptions)*.....

THE DEPUTY CHAIRMAN: No undue. Shuklaji, on this matter I would say that it is the

privilege of the Rajya Sabha Members to have a six-year terms. The Lok Sabha Members are welcome to get elected to Rajya Sabha and get the privilege of six years.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Madam, Lok Sabha Members are very reassured that their term is not going to end in two years or three years. It will be five years. And, therefore, these are the problems that the Lok Sabha Members have to face. They have to face the direct election and they have to go to each village for seeking votes and all that. But I am not going to go into all that. I am only saying that there are certain advantages that will come to the elder House and we do not grudge. I have advised the Lok Sabha Members, while I was speaking there, that they should bear with us and if the elders get a little more advantage, we should not grudge it....*(Interruptions)*...

श्रीमती सुषमा स्वराज: मैडम, पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब जो चाहे कहें, हमें तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जो चाहे कहें, पैसा देना है वित्त मंत्री ने। वित्त मंत्री राज्यसभा के मेंबर है। इसलिए अपने को तो 6 करोड़ मिलना ही मिलना है।

उपसभापति: ठाकुर साहब भी किसी हाऊस के मेंबर है।

श्रीमती सुषमा स्वराज: हां, वह भी इसी हाऊस के मेंबर है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have lot of privileges, Mr. Minister...*(Interruptions)*...

SHRI VIDYACHARAN SHUKLA: Yes, Madam, we do not want Members of parliament to get involved in giving out tenders and contracts and all that. It must be done by the Collectors according to the guidelines given by the State Governments and according to the rural development programmes and the programme of....*(Interruptions)*..

उपसभापति: जरा खामोशी से सुन लीजिए ना। इतनी सबको चिंता थी। अब बता रहे हैं तो सुन लीजिए। फिर आपको डाऊट्स रहेंगे।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: As long as Members have indicated the works on which the money has to be spent, the money would be allowed to be carried over to the next financial year. As long as the schemes are given and the schemes are announced and they are coming to the District Collectors, the schemes can be carried over to the next financial year. But there would be no accumulation allowed, that is, if in one year I don't give any scheme and in the next financial year I want to use Rs. 2 crores instead of one crore of rupees in one year, that will not be allowed. The schemes where this money will be used, should be indicated in the year and if the scheme is not finished in one year, it will be carried over to the next year. And, therefore, this kind of indication by hon. Members would be necessary.

Then, Mr. Salim was pleased to say that these are populist moves. These are not populist moves. All moves that have been made by us are for removal of poverty and development of rural areas in conjunction with all those schemes this scheme has also been made so that hon. Members can participate in these schems of public welfare, people's welfare schemes where the hon. Members will have a chance of participation and this will be a great and distinct advantage to the hon. Members.

The amount of money that can be spent on private charitable buildings or buildings belonging to various trusts, educational trusts, etc., whether this kind of money can be given to them for various purposes like adding rooms or anything like that, is something which is being considered. It has not been decided whether this should be allowed or not because we are very concerned about this matter that no M.P. should get any bad name or should not get into a controversy of any kind while utilising this scheme that has been devised. He will have an active participation in these public welfare schemes. About the Election Commissioner's query the common sense interpretation of such a situation is that after the notification of the elections, no such announcements can be made for this kind of schemes even though the notification of the election may be for the State Assembly and not for Parliamentary elections. I would advise hon. Members here to make this scheme for the entire year and announce it once and for all and not do it piecemeal which would be better, otherwise, they would unnecessarily stuck up with various kinds of things.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: शुक्ल जी, उसमें एक दिक्कत होती है, एस्टीमेट पता नहीं लगता।

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I am only giving an advice that you please do it in such a manner that it does not clash with the announcement of the elections by the Election Commissioner.

SHRI GOVINDRAM MIRI: One point....

THE DEPUTY CHAIRMAN: Miri saheb, this is not proper. Let him finish. No.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: As soon as the Members' schemes come to the Collector, within the guidelines, it will be properly spruced up and properly revised. As long as these schemes indicated by the hon. Member are within those guidelines, there is no question of the collector being able to say 'no' to these schemes. Any scheme suggested by the hon. Members will have to be implemented by the Collector concerned. There will be no discretion given to him to say that he cannot do this and he can do this, provided the scheme is within the parameters of the guidelines.

This expenditure is now being given under a different head and is being taken away from the district plan so that there is no complication of district plans being revised and this expenditure getting mixed up with the district plan. This will be a distinct head of expenditure and the Collectors will be spending money out of that.

There was a query that in case there is any problem with the Collector, where the M.P. can take the complaint to. Normally, the complaints should be taken to the Planning Department of the State Government concerned or to the Rural Development Minister of the State concerned. But I am sure, such contigencies will not arise and we will make the guidelines so clear that the implementing authority as will as the hon. Members will know exactly where to do what and this scheme will go through well.

And, lastly, Madam, I would like to say that its first year of operation will give us a good deal of experience. In the light of that experience in case any amendment or any improvement in the scheme is necessary, we shall certainly do that after collecting the suggestions and experience from various hon. Members.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. That matter is closed now.

बस, अभी पूरे विस्तार से बता दिया है।.....(व्यवधान)

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: One point that Mr. Swell made about the hill districts. As far as Members of the lok Sabha are concerned, they have no such problem because it is spread all over their constituencies. As far as Members of the Rajya Sabha belonging to the Hill Districts are concerned, we will consider what Dr. Swell has said in the matter and we will see what to do about it.

(Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN: We cannot go on.....

श्री गोविन्दराम मिरी: अभी आपने कहा कि विधान सभा चुनाव के लिए एम्बार्गो हो जाएगा तो क्या नगर-निगम के, नगरपालिका के चुनाव के लिए भी एम्बार्गो होगा?

श्री अनन्तराम जायसवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय मंत्री जी से मैं एक चीज़ जानना चाहता हूं आपके माध्यम से। छोटी-छोटी नदियां है एक गांव और दूसरे गांवों के बीच में और गांव और शहर के बीच में और उन पर अगर पुल बनाने की बात आती है तो कम से कम उस में पंद्रह-बीस लाख रुपए भी खर्च होते हैं और इस वक्त हम दस लाख रुपए ही कर सकते है तो क्या एसे मामलों में कोई छूट गाइडलाइन्स में शामिल करेंगे आप?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Madam, after a serious consideration, we have found that it will be better to keep the ceiling of Rs. 10 lakhs for one work given. But it can be repeated year after year, and it can be added up with the allotment made by the State Government. But I don't think that in one scheme, the entire money should go and the rest of the constituency should suffer. Therefore, this ceiling has been kept, and we intend to keep it.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Actually, the idea is that the MP should have some funds to spread over larger areas, for smaller schemes because building the bigger schemes is the responsibility of the State Government or the Central Government. It is just to help. You might say that you want 200 yard long route. You cannot do that.

SHRI ANAT RAM JAISWAL: There may be one or two exceptions.

उपसभापति: ऐक्सेप्शन की बात यहां मत कीजिए। अगर कोई ऐसी बात हो, बहुत जरूरी हो तो आप बात कर सकते हैं मगर

Generally, the scheme is a good scheme. The Members of Parliament would have now small projects of benefit for the people in the area where development is needed which is not generally covered in the larger schemes of the Development Plan, either of the State or the Centre. So, I think, it is a very welcome scheme. Mr. Minister, we once again thank you for coming here and explaining, and listening to everybody's queries and answering them. Thank you. *(Interruptions)* ठाकुर साहब तो हम लोगों के हैं, उनको रोज़ हम लोग कहते हैं।

Now, Bills for Introduction—Dr. Naunihal Singh.

SHRI G. SWAMINATHAN (Tamil Nadu): Madam, I am on a point of order. Shri V.N. Gadgil has to move for leave to withdraw his Bill. What happened to that?

THE DEPUTY CHAIRMAN: He is not here.

SHRI G. SWAMINATHAN: He was here all the time.

THE DEPUTY CHAIRMAN: At this point of time, he is not here. I call a Member who is there at that point of time. He is not here. So, I am calling Dr. Naunihal Singh.

THE SUGAR-CANE (AMENDMENT) BILL, 1994)

DR. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Sugar-Cane Act, 1934.

The question was put and the motion was adopted.

DR. NAUNIHAL SINGH: Madam, I introduce the Bill.

THE FARM PRODUCE PRICE FIXATION AUTHORITY BILL, 1994.

DR. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of an autonomous Authority for fixation of periodical minimum support prices of various farm produces like wheat, paddy, cotton, sugarcane, coarse grains, oil seeds, pulses, etc. for the entire country so that the farmers get remunerative prices for their produce and for matters connected therewith or incidental thereto.

The question was put and the motion was adopted.

DR. NAUNIHAL SINGH: Madam, I introduce the Bill.

THE INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 1994.

DR. NAUNIHAL SINGH (Uttar Pradesh): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian penal Code, 1860.

The question was put and the motion was adopted.

DR. NAUNIHAL SINGH: Madam, I introduce the Bill.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1994)

(to amend article 324)

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA (Uttar Pradesh): Madam, I beg tomove for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: I introduce the Bill.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1994

(to amend the Eighth Schedule)

SHRI SATYA PRAKASH MALVIYA (Uttar Pradesh) : I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: I introduce the Bill.